हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में हानि

@ *464. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, भिलाई द्वारा जो निर्माण-कार्य अपने हाथ में लिया जाता है, वह अपने ठेकेदारों से कराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में घाटा हो रहा है तथा इसमें कामगारों की छटनी की जा रही है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंष्ट्रक्शन लिमिटेड, भिलाई में अपने विभागीय श्रमिकों तथा ठेकेदार के श्रमिकों, दोनों की मार्फत निर्माण-कार्य कर रही है ।

(ख) ऐसे कुछेक कार्य हैं, जहां अनन्यरूप से विभागीय श्रमिकों द्वारा ही कार्य पूरा कराने के लिए अपेक्षित दक्षता और कुशलता प्राप्त श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते । जिसके परिणाम-स्वरूप कार्य को समय पर तथा ग्राहक द्वारा नियत लक्ष्य के अनुसार पूरा कराने के लिए ठेकेदारों को लगा कर कार्य पूरा कराना आवश्यक हो गया है ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को वर्ष 1978–79 से घाटा हो रहा है तथा 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी को 65.02 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है । इस समय किसी कामगार की छंटनी नहीं की गई है ।

@ पूर्वतः तारांकित प्रश्न 364, 28 नम्बर, 1986 से स्थगित ।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन के पास लगभग 2000 इंजीनियर और 23000 वर्कर हैं और 1964 से ले कर इन 22 वर्षों में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के लिये उन्होंने काफी कार्य क्षमता का संपादन किया है । परन्तु फिर भी अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जब उन का अपना वर्क फोर्स अधिक है, काम कम है फिर भी कुछ ऐसे रिक्यूजिट स्किल्स उन्होंने बताये कि जिस के कारण ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, अपने पास कार्यकर्ता होने के बाद भी, वर्कर होने के बाद भी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे रिक्वीजिट स्किल्स हैं जिन के लिये उन्होंने पेटी ठेकेदारों को काम दिया है और जिन के लिये हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन के पास आदमी नहीं हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभापति, जी 1964 में जब एच०एस०सी०एल० बना था तो स्थिति यह थी कि कई ठेकेदारों को काम दिया गया था इसलिये कि उन के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था । बाद में एक जगह काम खत्म होने लगा और दूसरी जगह काम था । वहाँ एच०एस०सी०एल० को काम मिला और उन्होंने चाहा कि वे पहली जगह से दूसरी जगह लग जायें लेकिन स्थानीय लोगों ने उस का विरोध किया और इस वजह से भी उन को इसमें कठिनाई पड़ी । अभी जो प्रश्न आपने आखिर में पूछा कि कौन से डिसिप्लिन में इस तरह के लोग नहीं हैं, मैं भिलाई की ही मिसाल उनको दूं । तो भिलाई में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का काम एच० एस० सी० एल० को मिला है, तो उसमें मैंने देखा कि भिलाई में जो डिपार्टमेंटल वर्क फोर्स है उसमें करीब पांच हजार लोग हैं । अब उसमें इलेक्ट्रिशंस भी हैं, आपरेटर्स भी हैं सिविल ट्रेड्स के यानी बढ़ई या मेसंस वगैरह, यह 140 हैं पांच हजार में से और हैल्पर्स में से एक हजार हैं, जिनमें से दो-तीन सौ आदमी इनके साथ लग सकते हैं । बाकी को रीट्रेन

करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिशंस सिविल वर्क्स वगैरह में नहीं आते, प्लम्बर्ज हैं, दूसरे मेसंस हैं ।

तो इसलिए इस तरह के इम्बैलेंस आ गये।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इधर एच० एस० सी० एल० में 65 करोड़ का घाटा हो चुका है वर्षानुवर्ष में और काफी बड़ी क्षमता में इसके पास कार्यकर्ता हैं । सेल का यह सब्सिडियरी है । परन्तु सेल के भी जो कांट्रेक्ट्स हैं, क्या कारण है इंडियन ट्यूब आयरन एंड स्टील कम्पनी का जो डिसमेंटलिंग आफ कोक ओवन प्लांट था और जो वाईजैग प्लांट का अभी टेण्डर हुआ, जो इसको न देकर दूसरे ठेकेदारों को दिया गया है, तो इसका कारण बताने की मंत्री महोदय कृपा करें ।

दूसरा जो मेरा प्रश्न इसके साथ है, वह यह है कि यदि काम का अभाव रहा, तो अभी आपने कहा है कि अभी आप किसी को रेट्रेंच नहीं करेंगे, काम देने की आपकी कोई योजना नहीं है, तो आगे आप की वर्कर्स को रेट्रेंच करने की कोई योजना है क्या ? यदि योजना है, तो कब से आप उनको न्यरेट्रेंच करेंगे या किसी अन्य काम में आपकी लगाने की योजना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभापति जी, यहां सेल का सब्सिडियरी नहीं है और जहां तक वाइजैग का प्रश्न है, कोशिश की गई कि वाइजेंग में यहां से लोग भेजे जाएं । बोकारो में जैसे-तैसे सरप्लस उत्पन्न हुआ, तो कोशिश हुई कि इधर-उधर भेजे जाएं । उसमें से कुछ लोग वाइजैग भी भेजे गये । मगर वाइजैग में उसके खिलाफ आन्दोलन हो गया बहुत कम लोग जा पाये कुछ लोग गये अभी हाल ही में भी हमने कुछ लोग भेजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं जा सकते और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं आपसे, मैंने खुद मैंने खुद कोशिश की है कि काम एच०एस० सी०एल० को मिले ताकि लोगों को रेट्रेंच करने की नौबत न आए, लेकिन सरप्लस है, इसमें कोई संदेह नहीं और अगर दूसरी जगह काम नहीं मिल पाया, पिछले दिनों में कुछ मिला है, और पोजिशन थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन अगर काम नहीं होगा, तो जाहिर है कि रेट्रेंच मेंट की बात भी आ सकती है । हमारी पूरी कोशिश होगी कि यह न हो, लेकिन मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन यह जरूर करूंगा कि सारे दलों को और सारी ट्रेड यूनियन्स को यह बात सोचनी होगी कि इस तरह के काम जोकि एक जगह अगर किसी योजना में लोग लगें हजारों की संख्या में और वह काम पूरा हो, तो वह हजारों आदमी दूसरी जगह जा नहीं सकते ।

इसलिए हमें गंभीरता से सोचना होगा कि कितनी बड़ी वर्कफोर्स इकठा इस आधार पर करें कि कुछ दिन तो इनको काम मिलने और उसके बाद उनको हटाना है और जब हटाने की बात आती है और रेट्रेंचमेंट की बात आती है, उस वक्त वह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है । इस पर सब को विचार करना होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, मैं पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसका घाटा 1978 में शुरू हुआ और 1986 तक 65 करोड़ 2 लाख का घाटा हो चुका है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 31-3-1986 को वहां पर कितने अधिकारी थे और वहां के कारगर इंजीनियरों की कितनी संख्या थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभापति जी, मालवीय जी ने तारीख दे दी । मैं तारीख नहीं देना चाहता था । 1977 में पहले यह मुनाफा कर रहा था, इत्तिफाक की बात है कि 1978 के बाद यह नुकसान करने लगा है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने पूछा था कि कितने अधिकारी और कितने इंजीनियर थे ? ... (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने तारीख नहीं दी । ... (**व्यवधान**) अब एक्सीक्यूटिव्ज जो हैं, दिसंबर 1984 में टोटल एक्सीक्यूटिव्ज हैं । 1,863, नान-एक्सीक्यूटिव्ज में 4,481 और वर्कर्ज में 17,281 कुल मिलाकर 23, 625 हैं

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Sir, the Finance Minister was stating that workers' participation. *(Intci*-ruptions)...I am just making a reference. In the House it was stated by the Finance Minister that workers, participation in management is the only solution to save industry from losses, to have better management and to see that all the work force is property utilized. All these things were told by him. So also, the contact system is one of the main causes for the the losses. I want to know what the steel Minister would like to say on these two points.

MR. CHAIRMAN: Employment of contract system is a cause for losses. .

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: About workers participation in management also.

SHRI K. C. PANT: Sir, workers participation in management is a much wider question and different question altogether. Here, so far as The employment of departmental labour is concerned, wherever it is possible we employ departmental work force. Where the required skills are not available we have to employ contractors; where time schedules are pressing and HSCL is not able to meet those requirements of the plants, then contractors are employed. I am also aware of the problems of the client because the steel plants are the clients. If there is a delay of six months because of HSCL then the country loses much more than it would save on account of not having a contractor and insisting on HSCL. So one has to take an overall view of this.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Sir, the problem of surplus in the construction field mainly arises because of misplanning. This is if we cannot foresee a rhythem in the growth of steel industry, then the steel construction workers sometimes emerge as aurplue and sometimes there is a shortage there. I do not know whether from this point of view if he will look into the matter of spreading over a time the output of steel itself. He is a competent Minister but I have not understood this on the question of contractors. Because, this is the trend in the railways also. Regular employees are replaced and contractors are being employed. When a contractor employs the workers, everybody knows that they get much less. If there is a problem with any transit, they should all be agreeable to transfer; no trade union will object to it. But if there is a resistance from local population, there is a problem there. In that case there can be a gap where the rules should be such that short-term recruitment should be possible in that area instead of depending on the contractor because contact with contractors, as we have indicated also, is a source of corruption, a source of inefficiency and a source of exploration. Will the Minister kindly consider these aspects and, if required, proceed to change the rules of speedy recruitment of local labour?

SHRI K. C. PANT: Sir, the background of the HSCL is a little different. When it began, it served a very good purpose. At that time there was no construction agency for steel plants in the public sector, and the private sector contractors were getting together and jacking up Prices. At that time HSCL definitely helped to keep prices down and introduced an element which controlled the prices of construction of those steel plants at that stage. But subsequently, till about 1977 — I find from the history— the number of workers was not very large. Thereafter, suddenly the number went up rapidly. Once it became 26,000. In fact, it went up and it is coming down. In 1978-79 it was 20,000. The total was 26,000, workers 20,000. In 1986-87 it has come down to 16,200 workers and the total has *come* down to

about 22,599. But that is still too large. And the question is not very relevant today. Today the question is, we have a surplus. We are not employing contractors' labour wherever it can be avoided. It cannot be avoided in all cases, as I mentioned. And the problem is of finding work for them. Otherwise, retrenchment becomes inevitable. It is to avoid that basic problem that we are trying to approach the State Governments and others to see that some work is given to them. So far, somehow we have managed. But the problem is acute, and I will require your full co-operation in this matter.

MR. CHAIRMAN: Question No. 465.

SHRI H. K. L. BHAGAT: (a) Yes, Sir, (b) The licencing policy...

MR. CHAIRMAN; No. no. Mr. Minister. You merely say, "A statement is laid on the Table of the House".

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sorry, Sir.

Irregularities ln NCCF, Delhi

465. SHRI BHAGATRAM MANHAR: SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: t

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared under the caption "NCCF working criticised" in the Business Standard dated the 16th June, 1986 highlighting the gross irregularities committed by the Delhi branch of the NCCF; and

(b) if so, what are the details thereof and what action Government have taken or propose to take in this regard?

t The question was actually asked on , the floor of the House by Shri Bir-Bhadra Pratap Singh.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT); (a) and (b) Yes, Sir. A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Reports of Irregularities in the NCCF, Delhi appeared in the 'Business Standard' 16-6-1986.

The news item appeared in the 'Business Standard' dated 16th June, 1986 referred to Audit Report, of the Delhi Branch of the NCCF for the year 1983-84 sent by the Joint Director of Audit as well as the request of Shri Virendra Verma, MP, made in his letter addressed to Prime Minister regarding super-session of the Board of the NCCF and weeding out corruption in the NCCF.

The Director of Audit, Commerce, Works & Miscellaneous, in his Audit Report of Delhi Branch of NCCF for the year 1983-84 has indicated certain irregularities committed by NCCF in the supply of pulses to FCI for Army Purchase Organisation, extending of credit in violation of the prescribed policy credit to unauthorised and fictitious parties, charging of lower rates from private parties than what was charged from Cooperatives, sale of goods to private parties at half of the cost price, shortage and pilferage in the godown stock, non-realisation of long outstanding claim and unauthorised reduction in the sale price of confiscated goods.

In so far as irregularities in the supply of pulses to FCI are concerned, on receipt of the complaints this Department referred the case to CBI for investigation. It has been reported by CBI that the Investigation has been concluded and the Report is under finalisation. With regard to other irregularities brought out in the Audit Report, NCCF has been asked to look into the matter and take appropriate action against officers responsible for such Irregularities.